SHAKTI

PUMPING LIFE

Date: -22/07/2024

To, The Secretary, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange plaza, BKC, Bandra (E) Mumbai-MH 400051.	To, The Secretary, Corporate Relationship Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai- MH 400001.

REF :-(ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol -SHAKTIPUMP

Sub:- Newspaper Publications of Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper cutting containing the extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 published on Monday, July 22, 2024 in the Business Standard (Hindi) and Economic Times (English) Edition.

Kindly take on record the above information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully

For Shakti Pumps (India) Limited

Ravi Patidar

Digitally signed by Ravi Patidar
DN: c=IN, o=Personal, title=8835, pseudonym=1333629442703236517d1gdBD6KT9lYg, 2.5.4.20=098e95d8507c2ee0b78e4884145eebb246409d3498f443b082c47a92a26382c6, postalCode=453331, st=Madhya Pradesh, serialNumber=31dde50601e6024b2732ca5972ed69c26147945af389098003ac14a4c85644de, cn=Ravi Patidar
Date: 2024.07.22 17:06:37 +05'30'

Ravi Patidar
Company Secretary

वर्ष 17
अंक 126
8 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

सोमवार, 22 जुलाई 2024
कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, **भोपाल,** मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

पृष्ठ 4

ऋण-जमा अनुपात जल्द कम करेगा एचडीएफसी बैंक

जयंत आचार्य पृष्ठ 2

चीन, आसियान देशों से सस्ता आयात है मुख्य चिंता

आज आर्थिक समीक्षा और 23 जुलाई को बजट

बिज़नेस स्टैंडर्ड मंगलवार के अंक में पेश करेगा 2023-24 की विस्तृत आर्थिक समीक्षा और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल। बुधवार के अंक में सुलझाई जाएंगी आम बजट की गुत्थियां। उस दिन पढ़िए कि वित्त मंत्री की मुट्ठी कितनी खुली, किस क्षेत्र पर कितना जोर रहा और विश्लेषकों की राय में बजट से अर्थव्यवस्था पर कितना तथा कैसा असर पड़ेगा।

एक नज़र

सरकार के सहयोगी दलों ने विशेष दर्जे की मांग की

संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में रविवार को कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोक सभा उपाध्यक्ष का पद मांगा और प्रतिष्ठित नीट सहित पेपर लीक से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाकर स्पष्ट संकेत दिया कि वह इस सत्र को हंगामेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। सरकार के सहयोगी दलों ने भी विशेष दर्जे का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत दिया। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार नियमों का पालन करते हुए संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। पृष्ठ 8

आम बजट, तिमाही नतीजों से तय होगी चाल

इस हफ्ते शेयर बाजार की दिशा आम बजट, कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा वैश्विक रुख से तय होगी। विश्लेषकों ने कहा कि इसके अलावा विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, डॉलर के मुकाबले रुपये का उतार-चढ़ाव तथा ब्रेंट कच्चे तेल के दाम भी बाजार की दिशा के लिए महत्त्वपूर्ण रहेंगे। बाजार के लिए अगला सबसे महत्त्वपूर्ण कारक 23 जुलाई, 2024 को पेश होने वाला आम बजट है। बजट में वृद्धि को बढ़ावा देने वाली नीतियों के जारी रहने की उम्मीद है। कई अन्य कारक भी बाजार की दिशा को प्रभावित करेंगे। इनमें कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे, घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़े और व्यापक रूप से वैश्विक बाजार का रुख शामिल है।

आज का सवाल

क्या आसियान देशों के लिए अलग-अलग हो शुल्क ढांचा?

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो Y और यदि न है तो N लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा
क्या इन्फोसिस के नतीजे आईटी क्षेत्र में तेजी के हैं संकेत?

हां	77%	नहीं	23%

बिज़नेस स्टैंडर्ड सर्वेक्षण में सीईओ ने जताई उम्मीद

बजट में व्यय, रोजगार पर जोर

बीएस संवाददाता
मुंबई/चेन्नई/कोलकाता, 21 जुलाई

भारतीय उद्योग जगत के अधिकतर मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अपने पहले बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने और ग्रामीणों/किसानों, खपत एवं रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा।

पिछले सप्ताह भारतीय उद्योग जगत के 20 सीईओ के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में 95 फीसदी प्रतिभागियों ने उम्मीद जताई कि इस केंद्रीय बजट में सरकारी खर्च से प्रेरित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट में नई सड़कों, एक्सप्रेसवे एवं अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की थी। यह रकम देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 3.4 फीसदी और एक साल पहले के मुकाबले करीब 11.1 अधिक है।

बजट पर सीईओ की राय

प्रश्न	हां	नहीं	कह नहीं सकता
क्या आपको लगता है कि बजट में पूंजीगत खर्च/बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा?	95 %	0 %	5 %
क्या बजट में रोजगार सृजन के लिए नीतिगत जोर दिया जाएगा?	75 %	15 %	10 %
क्या खपत बढ़ाने के लिए बजट में कर लाभ या छूट की उम्मीद है?	70 %	5 %	15 %
क्या आपको लगता है कि बजट में गांव/किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा?	70 %	15 %	15 %
क्या बजट में सुधारों को आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर बना रहेगा?	80 %	15 %	5 %

स्रोत: बीएस सीईओ सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में 20 सीईओ शामिल थे। संकलन : बीएस रिसर्च

सीमेंट बनाने वाली कोलकाता की प्रमुख कंपनी श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि परियोजनाओं के लिए अधिक रकम के अलावा राजमार्गों, सड़कों, पुलों और शहरी विकास के लिए खर्च में वृद्धि होगी। अंतरिम बजट में सीमेंट कॉरिडोर की घोषणा काफी उत्साहजनक रही है और हम परिवहन के एकीकरण को बेहतर करने के लिए विभिन्न उपायों की उम्मीद करते हैं ताकि सीमेंट और संबंधित सामग्री की निर्बाध एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके।'

इसी प्रकार 80 फीसदी प्रतिभागियों ने उम्मीद जताई कि सरकार आर्थिक सुधारों को जारी रखेगी। इससे वृद्धि को रफ्तार देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने और कारोबारी सुगमता को बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत हर साल 110 अरब डॉलर के एफडीआई निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रख रहा है। हालांकि साल 2023 में देश में एफडीआई निवेश 43 फीसदी घटकर 28 अरब डॉलर रह गया था, जबकि वैश्विक गिरावट 2 फीसदी रही थी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

सर्वेक्षण में शामिल 70 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार खपत को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश करेगी। इतनी ही तादाद में प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि ग्रामीण बाजार और किसानों पर सरकार का फोकस जारी रहेगा।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आसियान देशों के लिए अलग-अलग शुल्क ढांचा!

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 21 जुलाई

व्यापार का मसला

- भारत द्विपक्षीय करार में रियायत देने के लिए अलग-अलग देशों के लिए अलग शुल्क रखने की संभावना तलाश रहा
- फिलहाल सभी आसियान देशों के लिए एक ही तरह का शुल्क है
- आसियान देशों के साथ व्यापार करार की समीक्षा बैठक का तीसरा दौर 29 से 31 जुलाई को इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा

भारत सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में शामिल 10 देशों में से प्रत्येक को द्विपक्षीय रियायतें देना चाहती है। इसके लिए वह नरमी की संभावना तलाश रही है, जिस पर आसियान देशों के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक में विचार किया जाएगा। इस व्यापारिक करार पर भारत ने 13 साल पहले हस्ताक्षर किए थे।

आसियान देशों के साथ व्यापार करार की समीक्षा बैठक का तीसरा दौर 29 से 31 जुलाई को इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा। दोनों पक्ष 2025 तक समीक्षा पूरी करने के पक्ष में हैं।

अगर इस पर सहमति बनती है तो आसियान के दसों देशों को एकसमान शुल्क ढांचे के बजाय अलग-अलग रियायतें मिल सकती हैं। इससे भारत को बेहतर सौदे हासिल करने में मदद मिलेगी और उन क्षेत्रों में देसी हितों की रक्षा भी होगी, जहां आसियान देशों की बाजार पैठ बढ़ने से नुकसान हो सकता है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'अगर भारत एक शुल्क ढांचा रखता है तो दिक्कत रहेगी क्योंकि हो सकता है कि 8 देशों को किसी क्षेत्र में प्रवेश देना फायदेमंद हो मगर बाकी दो देशों के लिए ऐसा करना सही नहीं हो।' आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर चलता है, जिसमें हरेक सदस्य देश के लिए अलग-अलग शुल्क रखा जा सकता है।

(शेष पृष्ठ 4)

अदालत के दखल से राहत के संकेत

बांग्लादेश में रोजगार कोटा के विरोध में हुए हमलों में 133 लोगों के मारे जाने के बाद वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को इस मामले में दखल किया। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने सरकारी नौकरियों में अधिकांश कोटा खत्म कर दिया। खबरों के अनुसार 93 फीसदी सरकारी नौकरियां बिना कोटा के योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। न्यायालय के हस्तक्षेप को भारतीय कंपनियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में काम कर रही इमामी और इंडोफिल जैसे कंपनियों को विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू के कारण अपने संयंत्र बंद करने पड़े। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के आंकड़े के अनुसार इस पड़ोसी देश में निवेश करने वाली कंपनियों में मैरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प प्रमुख हैं। पृष्ठ 2

तीसरे दिन भी उड़ानों पर असर

माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में शुक्रवार को आए व्यवधान से भारत में विमानों की आवाजाही पर व्यापक असर पड़ा था। रविवार को भी उड़ानों में देर की समस्या बनी रही। मुंबई में भारी बारिश से भी उड़ानें प्रभावित हुईं। माइक्रोसॉफ्ट संकट के कारण शुक्रवार और शनिवार को भारत में 400 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, जिनमें से करीब 300 इंडिगो की थीं। हालांकि रविवार को उड़ानें रद्द करने के मामले कम देखे गए मगर उड़ान में देर की समस्या बनी रही। सूत्रों ने कहा कि अगले दो दिन में परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। स्पाइसजेट और अकासा एयर ने कहा कि तीन दिन में उसकी एक भी उड़ान रद्द नहीं हुई है मगर समय पर आवागमन पर असर पड़ा है। पृष्ठ 2

कंपनियों के मुनाफे में नरमी के संकेत

कृष्ण कांत
मुंबई, 21 जुलाई

पहली तिमाही के नतीजों का विश्लेषण

- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों की आय घटने से मुनाफे पर भी दिखा दबाव
- विश्लेषकों ने कहा कि पूरे वित्त वर्ष के लिए आय वृद्धि के अनुमान में की जा सकती है कटौती
- कच्चे माल की लागत बढ़ने से मार्जिन पर भी दबाव
- आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में दिख रहा सुधार

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अभी तक कंपनियों के जो नतीजे आए हैं उनसे कंपनियों की आय और मुनाफे में नरमी का संकेत मिलता है। आंकड़ों से पता चलता है कि आय वृद्धि घटने और वित्त वर्ष 2024 में मिलने वाला जिंसों एवं ईंधन की कम कीमतों का लाभ खत्म होने से मुनाफे पर दबाव दिख रहा है।

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए नतीजे जारी करने वाली 210 कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही से 4.2 फीसदी कम रहा। यह पिछली सात तिमाही का सबसे खराब प्रदर्शन है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में इन कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा 45.1 फीसदी बढ़ा था और इसी वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 4.4 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई थी।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इन कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा 88,723 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही के 97,768 करोड़ रुपये से 9.3 फीसदी कम है। वित्तीय क्षेत्र से इतर कंपनियों का प्रदर्शन और भी खराब रहा। बैंक, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) कंपनियों को हटा दें तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 160 फर्मों का कुल शुद्ध मुनाफा 10.2 फीसदी घटकर 57,599 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 64,109 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में बीएफएसआई और तेल एव गैस क्षेत्र की 158 कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 5.6 फीसदी बढ़कर 39,516 करोड़ रुपये रहा। तेल गैस कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आंकड़ा शामिल है जिसका शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.5 फीसदी घटा है।

तिमाही आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बीएफएसआई कंपनियों की अगुआई में कुल आय वृद्धि में कमी आई है जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो जैसी आईटी कंपनियों की आय बढ़ी है।

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में नतीजे जारी करने वाली कंपनियों की कुल शुद्ध आय इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 8.2 फीसदी बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही की 6.4 फीसदी वृद्धि से ज्यादा है। मगर वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही की 8.6 फीसदी वृद्धि से कम है।

हमारे नमूने में शामिल 50 बीएफएसआई कंपनियों की सकल ब्याज आय वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 14.8 फीसदी बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपये रही, जो पिछली आठ तिमाही में सबसे कम वृद्धि है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

SHAKTI PUMPING LIFE

SHAKTI SOLAR PUMPS
INNOVATION THAT BENEFITS ALL

ORDER BOOK
INR 2000* CR

FINANCIAL HIGHLIGHTS Q1 FY 25 VS Q1 FY 24

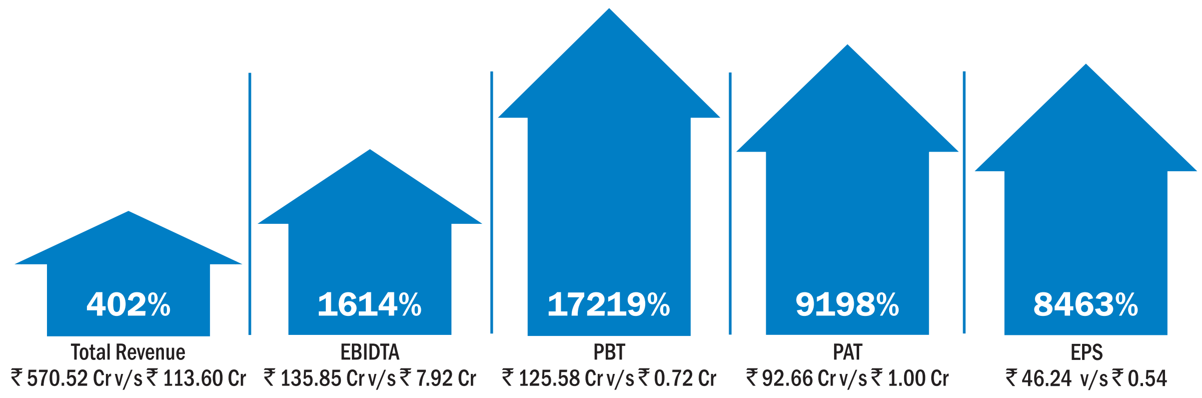

STATEMENT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2024

(Rs. In Crores, unless otherwise stated)

S.No	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter Ended on			Year ended on	Quarter Ended on			Year ended on
		June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024	June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operation (Net)	570.52	610.13	113.60	1,374.31	560.31	588.04	108.87	1,303.23
2	Net Profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	125.58	119.03	0.72	189.89	121.50	96.61	3.51	158.69
3	Net Profit/(loss) for the period before tax after exceptional items	125.58	119.03	0.72	189.89	121.50	96.61	3.51	158.69
4	Net Profit/(loss) for the period after tax	92.66	89.64	1.00	141.71	90.49	70.96	4.41	117.14
5	Total Comprehensive Income for the period	92.85	89.08	1.08	141.69	90.54	70.39	4.41	116.57
6	Equity share capital	20.04	20.04	18.38	20.04	20.04	20.04	18.38	20.04
	(Face Value: Rs.10/- per share)								
7	Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each for continued and discontinued operations								
	(1) Basic	46.24	48.66	0.54	76.91	45.17	38.51	2.40	63.58
	(2) Diluted	46.24	48.66	0.54	76.91	45.17	38.51	2.40	63.58

- The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 20, 2024.
- Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
- The results above are mentioned in Rs Crores, similarly the previous year figures have also been reported in Rs Crores.

*Executable over next 15 months.

Place : Indore
Date: 20th July, 2024

देश का पम्प शक्ति सोलर पम्प
SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

For: Shakti Pumps (India) Limited
SD/-
Dinesh Patidar
Chairman & Whole Time Director
(DIN: 00549552)

CIN : L29120MP1995PLC009327 | Web: www.shaktipumps.com | E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com
Corporate Office : Plot No. C-04, Silver Spring, Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opp D Mart, Indore-452020. (M.P.) INDIA. Tel.: +91 731 3635000
Regd. Office / Factory Add. : Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur-454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA. Tel.: +91 7292 410500

AT LEAST 114 PEOPLE KILLED IN PROTESTS; BANGLADESH SC SCRAPS QUOTA

Indian Interests at Stake as Bangladesh Remains Tense

So far, over 4,500 Indian students have returned to India

Dipanjan Roy Chaudhury

Students clash with police during a protest over the quota system for government job applicants, in Dhaka – AP

New Delhi: Indian interests are at stake with the Bangladesh situation remaining tense and volatile, notwithstanding the decision by the country's Supreme Court on Sunday to scrap the student reservation policy which is the genesis of the current crisis.

Opposition BNP through the Jamaat-e-Islami has threatened to unseat the Hasina government and has launched a campaign to influence the country's Army to prevent it from safeguarding the dispensation. A fake letter signed by "junior officers" of Bangladesh Army was circulated with an aim to pressurise the Army Chief to take a neutral stand. Dhaka-based sources told ET that the country's security establishment is backing Prime Minister Sheikh Hasina.

Bangladesh Supreme Court ordered that veterans' quota be cut to 5%, with 93% of jobs to be allocated on merit

On Sunday Bangladesh's Supreme Court scrapped most of the quotas that have sparked protests and in which at least 114 people have been killed. The Supreme Court's Appellate Division dismissed a lower court order that had reinstated the quotas, directing that 93% of government jobs will be open to candidates on merit, without quotas, reports said.

The Hasina-led government had scrapped the quota system in 2018, but the lower court reinstated it last month, sparking the protests that were later hijacked by the radicals and BNP. The students have also put forward a nine-point demand agenda that includes an apology from the PM, sacking of two senior ministers and certain concessions to students.

Sources from Dhaka said that the Hasina government is reviewing the demands.

In New Delhi, top brass of the Indian government is closely monitoring the situation. Instability and unrest in Bangladesh have a direct impact on India's security and economic interests in West Bengal and Northeast. Experts on Bangladesh, who did not wish to be quoted, feared that the anti-Hasina movement could transform into an anti-India movement unless the situation is handled deftly. Strengthening of radical forces in Bangladesh is inimical to India's interests.

'DOORS OF WEST BENGAL OPEN'

Will Offer Shelter to Anyone in Distress, Says CM Banerjee

Our Political Bureau

Kolkata: West Bengal chief minister Mamata Banerjee on Sunday said in wake of the violence in Bangladesh, she would keep the doors of her state open for people in distress and offer them shelter, referring to the United Nations resolution on refugees.

"If someone knocks at my door seeking refuge due to trouble in Bangladesh, I will give them shelter," Banerjee said, adding, "Don't worry if you have family members in Bangladesh, or people who have come here and got stuck, we will help them. If people come here in a helpless state and the people knock at the door of Bengal, we will surely give them shelter. We will not step in or talk about it as Bangladesh is a sovereign and the Indian government will speak about it. Our empathy and solidarity are with people and students as many lives were lost," Banerjee said. "We are sad to see so many deaths and my heart goes out to those students who were killed," she further said. "I should not be speaking on the affairs of Bangladesh as it is a subject matter of the Centre," Banerjee added.

The West Bengal CM's comments came amid the ongoing protests in Bangladesh that erupted over demands of an end to a quota system that reserves up to 30% government jobs for relatives of veterans who fought in Bangladesh's war of independence in 1971 against Pakistan. Addressing people during the 'Martyrs Day' rally of the Trinamool Congress in Kolkata, Banerjee also appealed to the people of West Bengal to not get provoked over matters concerning the current situation in the neighbouring country.

Comments 'Misplaced', says Govt on Bengal CM

New Delhi: The Centre on Sunday stated that comments by the West Bengal chief minister on Bangladesh are totally misplaced.

"These are matters which are handled by the Union government. A state government has no locus standi on the issue and as such their comments are totally misplaced," a source said. – OPB

ON 2-DAY VISIT TO MAHARASHTRA

No Need to be Despondent After Poor LS Results: Shah to BJP Workers

Asks cadre to put its disappointment to use & work for Assembly polls

Krishna Kumar

ANI

Mumbai: Trying to boost the morale of the BJP cadre after a demoralising performance during the recent Lok sabha polls in Maharashtra, home minister Amit Shah on Sunday said the party would be in power for the next 30 years at the Centre.

Addressing a state BJP conclave in Pune, Shah said, "In my two days (in Maharashtra), I have met a number of cadres and I have seen a bit of confusion, this is due to the misconception created by the opposition."

Shah is on a two-day visit to Maharashtra to bolster and oversee the party's campaign for the upcoming assembly polls.

Shah asked the party workers to not be despondent as the BJP has come back to power for the third time at the Centre. The BJP leader compared the Congress to a badly performing student who was happy that he got more marks even though he had failed again. "The cadre was working hard, so they felt a bit of a pain... However, don't be disappointed. I have to tell you that we were once at just 2 Lok Sabha seats and Rajiv Gandhi taunted us by saying 'Hum do hamare do'. There is no need for being disappointed, don't believe in the misconceptions spread by the opposition. That the BJP-led leadership in the state will bring the Maha Yuti back to power is confirmed," he Shah. The BJP leader said that the party cadre should use its disappointment to work harder for the assembly polls to ensure that the BJP wins by even bigger numbers.

Calling NCP-SP chief Sharad Pawar as "chief of corruption", Shah said, "You (Sharad Pawar) are accusing us of corruption... You are the biggest chief of corruption. If anyone has institutionalised corruption, it is you."

SHAKTI
PUMPING LIFE

SHAKTI SOLAR PUMPS
INNOVATION THAT BENEFITS ALL

ORDER BOOK
INR 2000* CR

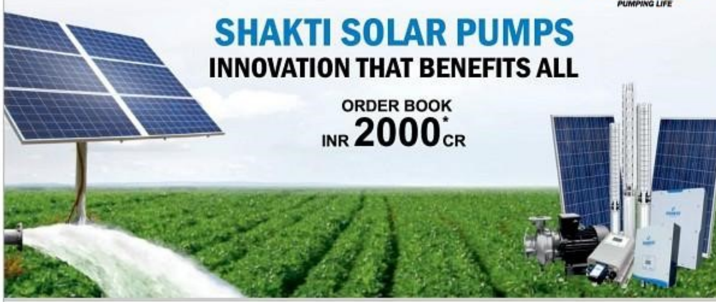

FINANCIAL HIGHLIGHTS Q1 FY 25 VS Q1 FY 24

Total Revenue ₹ 570.52 Cr v/s ₹ 113.60 Cr | EBIDTA ₹ 135.85 Cr v/s ₹ 7.92 Cr | PBT ₹ 125.58 Cr v/s ₹ 0.72 Cr | PAT ₹ 92.66 Cr v/s ₹ 1.00 Cr | EPS ₹ 46.24 v/s ₹ 0.54

STATEMENT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2024

(Rs. In Crores, unless otherwise stated)

S.No	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter Ended on			Year ended on	Quarter Ended on			Year ended on
		June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024	June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operation (Net)	570.52	610.13	113.60	1,374.31	560.31	588.04	108.87	1,303.23
2	Net Profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	125.58	119.03	0.72	189.89	121.50	96.61	3.51	158.69
3	Net Profit/(loss) for the period before tax after exceptional items	125.58	119.03	0.72	189.89	121.50	96.61	3.51	158.69
4	Net Profit/(loss) for the period after tax	92.66	89.64	1.00	141.71	90.49	70.96	4.41	117.14
5	Total Comprehensive Income for the period	92.85	89.08	1.08	141.69	90.54	70.39	4.41	116.57
6	Equity share capital	20.04	20.04	18.38	20.04	20.04	20.04	18.38	20.04
	(Face Value: Rs.10/- per share)								
7	Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each for continued and discontinued operations								
	(1) Basic	46.24	48.66	0.54	76.91	45.17	38.51	2.40	63.58
	(2) Diluted	46.24	48.66	0.54	76.91	45.17	38.51	2.40	63.58

- The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 20, 2024.
- Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
- The results above are mentioned in Rs Crores, similarly the previous year figures have also been reported in Rs Crores.

*Executable over next 15 months.

Place : Indore
Date: 20th July, 2024

देश का पम्प शक्ति सोलर पम्प
SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

For: Shakti Pumps (India) Limited
SD/-
Dinesh Patidar
Chairman & Whole Time Director
(DIN: 00549552)

CIN : L29120MP1995PLC009327 I Web: www.shaktipumps.com I E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com
Corporate Office : Plot No. C-04, Silver Spring, Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opp D Mart, Indore-452020. (M.P.) INDIA. Tel.: +91 731 3635000
Regd. Office / Factory Add. : Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur-454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA. Tel.: +91 7292 410500

Joe Biden Bows Out of Presidential Race... What Happens Next?

Washington: President Joe Biden said on Sunday he would withdraw from the 2024 presidential election race, putting the United States into uncharted territory. Biden endorsed Vice President Kamala Harris to be the Democratic nominee this year. Before Biden's decision was made, *Reuters* spoke to Elaine Kamarck, a senior fellow at the Brookings Institution think tank, a Democratic National Committee member, and author of the book 'Primary Politics' about the presidential nominating process, about what could happen next.

AP

WHAT HAPPENS NOW?

Biden has spent the last several months accruing nearly 4,000 Democratic delegates by winning primary elections in US states and territories. Those delegates would normally vote for him to be the party's official presidential nominee at the Democratic National Convention that is set to take place August. 19-22, but the rules do not bind or force them to do so. Delegates can vote with their conscience, which means they could throw their vote to someone else. By stepping aside, Biden is effectively "releasing" his delegates, potentially sparking a competition among other Democratic candidates to become the nominee.

WHO COULD REPLACE BIDEN?

Several candidates could step into the fray. Vice President Kamala Harris is at the top of the list, but she has had her own problems after a rocky start in the job and poor polling numbers. The US Constitution dictates that the vice president becomes president if the president dies or becomes incapacitated, but it does not weigh in on an inter-party process for choosing a nominee. California Governor Gavin Newsom, Michigan Governor Gretchen Whitmer, Kentucky Governor Andy Beshear and Illinois Governor JB Pritzker have all been floated as possible replacements. Up until now they have been Biden supporters working to help get him elected.

HOW WILL A NOMINEE BE CHOSEN?

There could be a free-for-all of sorts between the Democratic heavyweights vying for the job. According to Ballotpedia, there are expected to be some 4,672 delegates in 2024, including 3,933 pledged delegates and 739 so-called superdelegates — senior party members. In order to secure the nomination, a candidate would need to get a majority - that is, more votes than all the others combined. If no one achieves that, then there would be a "brokered convention" in which the delegates act as free agents and negotiate with the party leadership. Rules would be established and there would be roll call votes for names placed into nomination. It could take several rounds of voting for someone to get a majority and become the nominee. The last brokered convention when Democrats failed to nominate a candidate on the first ballot was in 1952.

WHAT HAPPENS TO CAMPAIGN CASH?

The Biden-Harris campaign had $91 million in the bank at the end of May, but experts on campaign finance law disagree on how readily the money could change hands. Because Harris is also on the campaign filing documents, many experts believe the money could be transferred over to her if she is on the ticket. **Reuters**

No Large-scale Irregularities in NEET-UG Test: Govt

Govt officials maintain 'breach' of examination paper was 'localised'

Our Political Bureau

New Delhi: A day after the National Testing Agency (NTA) published the full results of the National Eligibility-cum-Entrance Test (Undergraduate) 2024 on its website, the Centre has maintained its claim that there is no evidence of any large-scale irregularities in the examination.

Preliminary analysis of the data indicated that the highest number of students with highest scores are from Rajasthan, with as many as 482 students securing 700 plus score. A similar score was secured by 205 students in Madhya Pradesh; 194 in Kerala and 184 in Uttar Pradesh.

Government sources have rejected the apprehensions that irre-

only at one centre in Bihar. "Despite the breach at one centre in Bihar and hiring seven solvers, the beneficiaries (students) of wrongdoing could not benefit substantially," said a government official on the condition of anonymity. When asked about the high scores secured by students in Rajasthan, he added, "Rajasthan is home to coaching centres, in Kota and Sikar. It would be wholly wrong to suggest that a breach took place at centres in Rajasthan or elsewhere." He further said that the high scores secured by students at such centres is an outcome of their preparation and not a breach or any irregularity. As regards Gujarat, the Central Bureau of Investigation (CBI) has maintained that the alleged irregularities in the Gujarat centre pertain only to "cheating and impersonation."

CBI is likely to share the information with regard to its questioning of the seven solvers with Supreme Court today

The CBI has already submitted two status reports to the Supre-

ET ECONOMIC TIMES.COM

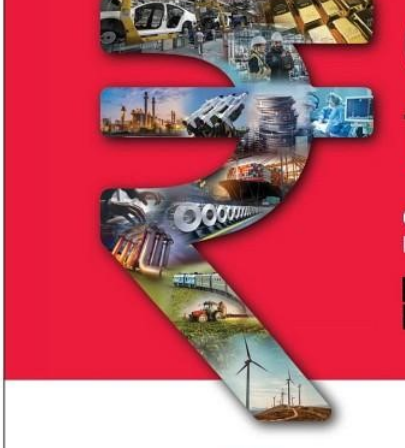

oadmap
to the century

CHARTING THE ECONOMIC AGENDA FOR INDIA IN THE BUDGET' 24.

Catch the most exhaustive budget coverage **LIVE** tomorrow on www.economictimes.com and the ET App.

BUDGET 3.0

1.44 billion Indians are looking forward to this year's budget. We are certain that Budget'24 will not only chart the path for future, but also boost the economy so that it meets all the milestones, before the centennial celebrations begin in 2047.